

मौत का व्यापार



भारत की भलाई के नाम पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मकड़जाल बुना गया जिसमें धीरे धीरे पूरा भारत आर्थिक और स्वास्थ्य के धरातल पर फँसता जा रहा है। प्रस्तुत लेख भाई राजीव दीक्षित जी के एक भाषण का लिखित स्वरूप है जिसमें मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा की गई है। आप इस व्याख्यान को श्रद्धेय भाई राजीव जी के श्रीमुख से नीचे दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं।

ऑडियो लिंक: https://docs.google.com/file/d/0B8n_36gK-KF4VjYyU2poVWVOanM/edit?usp=sharing

1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। इसके साथ साथ भारत में खाद और कीटनाशक के नाम पर जहर भी बिकना शुरू हुआ। ये

कृत्रिम रसायन खाद, कीटनाशक और जंतुनाशक के रूप में खेतों में डाले जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 वर्ष में 1 करोड़ 90 लाख रासायनिक खाद भारत भूमि पर डाला जाता है। सरकार का कहना है कि 90,000 मेट्रिक टन कीटनाशक प्रतिवर्ष भारत के खेतों में छिड़का जाता है। भारत में 786 से ज्यादा कृत्रिम कीटनाशक तथा 215 से अधिक जंतुनाशक प्रयोग किए जाते हैं। पूरे विश्वभर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि कैंसर उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख घटक कृत्रिम खाद और जंतु-कीटनाशक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में प्रतिवर्ष एक व्यक्ति 200 मिलीग्राम जंतु-कीटनाशक और 1 किलो 700 ग्राम रासायनिक खाद से प्राप्त होने वाले जहर को खा जाते हैं। रासायनिक खाद का 91-92% तथा जंतु-कीटनाशक का 96-97% व्यर्थ जाता है और जहर के रूप में हमारे शरीर, मिट्टी और पानी को जहरीला बनाता है! हमारे देश में प्रतिवर्ष 76,000 किसान इन कीटनाशकों को अधिक छिड़कने के कारण मारे जाते हैं। इनमें से अधिकतर तो अस्पताल जाते समय ही दम तोड़ देते हैं और जो पहुंच जाते हैं उनका बचना सुनिश्चित भी नहीं होता क्योंकि भारत में गरीबी के कारण ये दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

पूरे भारत में सबसे अधिक जहरीले खाद और कीट-जंतुनाशक का उपयोग पंजाब में किया जाता है जहाँ प्रति एकड़ खेत में 113 किलो खाद डाली जाती है। पंजाब में भी भटिंडा में सबसे ज्यादा जहर डाला जाता है और यहीं सबसे अधिक कैंसर के मरीज भी हैं। भटिंडा से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है जिसमें कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने बीकानेर जाते हैं। लोग इसे कैंसर ट्रेन के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इसमें लगभग सारे लोग कैंसर के शिकार हैं! इसके बाद नंबर है जालंधर, होशियारपुर और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहाँ सबसे अधिक रासायनिक खाद डाली जाती है और कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। इन जहरीले खाद और कीट-जंतुनाशकों को अमरीका, जर्मनी, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, चीन, रूस जैसे 24 देशों की 1000 बड़ी कंपनियाँ भारत में बनाती हैं। इस खाद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये फसल की प्रतिरोधक क्षमता को हानि पहुंचाती है जिससे फसल कमजोर हो जाती है। क्या आपको पता है कि Endosulphan नामक जहरीले कीटनाशक को जापान और अमरीका जैसे 56 से

ज्यादा देशों ने बंद कर दिया है। वहाँ इस जैसे 1000 जहर को बनाना और बेचना दोनों गैर कानूनी है परंतु इन्हीं देशों की कंपनियाँ भारत में इस जहर को बनाती और बेचती हैं!

वैज्ञानिकों का यह कहना है कि Endosulphan की थोड़ी सी मात्रा एक आदमी को मारने के लिए काफी है! ये जहरीले खाद और कीट-जंतुनाशक genetic disorder, दिमागी और खून की विकृति तथा कैंसर के कारक है। आपने देखा होगा कि आज कल अंगूरों पर सफ़ेद रंग का एक पाउडर लगा होता है जो कितना भी धोने के बावजूद नहीं हटता। यह Oxalic Acid नाम का जहर होता है। पहले तो ये विदेशी कंपनियाँ इस तरह का जहर बेच कर फसल कमज़ोर करती हैं जिससे उनमें कीड़े लगते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, फिर उसके लिए ये जहरीले कीट-जंतुनाशक बेचते हैं जिनसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं और उसके बाद उन बीमारियों की दवाइयाँ भी खुद बेचती हैं 1000% के लाभान्श तक! क्या आपको पता है कि कैंसर की जितनी दवाइयाँ भारत में बिकती हैं, वे अमरीका और यूरोप से पेटेंट प्राप्त हैं? राम विलास पासवान जब इस मंत्रालय में थे तो उन्होंने चार साल इस बात के लिए संघर्ष किया कि इन दवाइयों से पेटेंट हटा लिया जाए ताकि भारत खुद इन दवाइयों को बना सके और अपने देश के लोगों को सस्ते में उपलब्ध करा सकें लेकिन उनकी एक नहीं चली! कारण? ऐसी बातों के लिए संसद में बहुमत चाहिए होता है और दवा बनाने वाली इन विदेशी कंपनियों ने सारे सांसदों के मुँह नोटों से बंद किए हुए हैं! जहरीले खाद और कीट-जंतुनाशक बनाने वाली कंपनियों का तर्क है कि ये जहर यदि नहीं डालेंगे तो फसल को कीड़े बर्बाद कर देंगे। सच तो यह है कि यदि इस जहर को खेतों में न डाला जाए तो भारत का नुकसान 1500 करोड़ का होगा। वहीं इस 1500 करोड़ की बर्बादी को रोकने के लिए हमारी सरकार 5 लाख करोड़ का नुकसान हर साल उठती है, इन कंपनियों की कमाई के रूप में!

ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही यह षड्यंत्र चल रहा है। भारत जैसे विश्व के 150 से ज्यादा गरीब देशों में यही षड्यंत्र चल रहा है जिसमें इण्डोनेशिया,

अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। जहरीली खाद और कीट-जंतुनाशक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ अंतिम विश्व युद्ध के बाद से। अंतिम विश्व युद्ध के बाद अमरीका और यूरोप के देशों में यह समस्या थी कि बचा हुआ रासायनिक हथियार कहाँ उपयोग में लाया जाए। शोध करने पर पता चला कि इस रसायन का उपयोग खाद और कीटनाशक बनाने में हो सकता है। दो ही दशक में इन देशों को समझ में आ गया कि ये खाद और कीटनाशक जंतुओं को मारें न मारें, पर इंसानों को जरूर मार देंगे जिसके चलते इन्होंने इस जहर का निर्माण बंद कर दिया! अगला सवाल यह था कि अब जो तैयार हो चुका है, उसका क्या करें? इसके लिए उन्होंने भारत जैसे गरीब देशों को चुना। मंत्रालयों ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी और इस तरह ये जहर भारत में आए। क्योंकि इनका निर्माण विदेशों में बंद है और साथ ही भारत जैसे देशों में जानकारी के अभाव में मांग भी है, ये जहर भारत में ही तैयार होने और बिकने लगे!

पिछले दो दशकों में भारत में इन जहरीले तत्वों पर खोज हुई है और जैविक कृषि को ही सर्वोपरि माना है। कुछ कम संख्या में ऐसे किसान तैयार हुए हैं जिन्होंने जैविक कृषि शुरू की है और अपनी फसल को कई गुणा बढ़ाया है जिससे उनके लाभ में भी वृद्धि हुई है। अब समय है कि हम देश की जनता इस षडयंत्र के प्रति होशियार हों और जैविक खेती से पैदा हुए फलों और सब्जियों की मांग पैदा करें! इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि जब भी बाजार जाएँ तो फल-सब्जी वाले से यह पूछें कि यह जहरीली है या organic है। आज कल आपको organic फल-सब्जियाँ बहुत आसानी से मिल जाएँगी। ऐसा विकल्प मिलते ही आप उन फलों और सब्जियों को खरीदें। इससे जैविक फल-सब्जियों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी जिससे किसान अधिक से अधिक इस पद्धति को अपना कर देश की धरती को विषमुक्त बना पाएँगे!

मौत का व्यापार करने वाली कंपनियाँ एक और चीज बनाती हैं - सिगरेट। सिगरेट को सबसे पहली बार स्पैनिश लोगों ने अमरीका में बनाया, 16वीं शताब्दी में। स्पेन का एक लुटेरा जिसका नाम कोलंबस था, उसकी अगुवाई में

यह काम अमरीका में शुरू हुआ। ऐसी कई अमरीकी कंपनियाँ हैं जो सिगरेट तैयार करती हैं जैसे Phillip-Morris, R.J Reynold, American Tobacco Company। ATC (American Tobacco Company) जिस देश में जाती है, उसी देश के नाम से व्यापार करती है जैसे भारत में इसका नाम ITC (Indian Tobacco Company) है। आज कल यह कंपनी कपड़े से लेकर खाने पीने की चीज़ें भी बनाने लगी है! धूम्रपान करने वालों से ज्यादा बीमार उनके साथ धूम्रपान करते समय संपर्क में आए हुए लोगों को होता है। कैंसर पैदा करने में विषैली खाद और कीटनाशक के बाद दूसरा स्थान सिगरेट का है! ये सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ शक्तिशाली विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। फिल्मों और विज्ञापनों में ऐसे दिखाया जाता है कि सिगरेट पीने वाले कितने जोशीले होते हैं! इन विज्ञापनों को देखकर युवावर्ग सिगरेट पीने के लिए प्रेरित होता है। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में प्रतिदिन 1 लाख और भारत में 3000 युवा सिगरेट पीना शुरू करते हैं! जहाँ 16वीं शताब्दी में कोई सिगरेट नहीं पीता था वहीं 500 सालों में प्रतिवर्ष 5500 अरब सिगरेट बिक जाती हैं! पूरी दुनिया में 142 करोड़ सिगरेट पीते हैं तथा भारत में 20 अरब सिगरेट हर साल बिक जाती हैं! 1 सिगरेट को बनाने में 20 पैसे की लागत आती है जबकि वही एक सिगरेट 5-10 रुपए में बिकती है। सिगरेट को भारत में बिकवाने में नेता और प्रचारक की बहुत अहम भूमिका होती है। नेता इस पर रोक नहीं लगाते और नशे के इस कारोबार को चलने देते हैं यह कहकर कि इससे राष्ट्र की आमदनी होती है। किस काम की है यह आमदनी जब यहाँ के लोग ही जिन्दा नहीं बचेंगे? क्या भारत की आमदनी हमेशा से नशे के व्यापार से ही होती रही है? जब सिगरेट और शराब नहीं थे तो क्या भारत भूखा नंगा देश था? आज 1320 सिगरेट चीन में, 1670 सिगरेट अमरीका में, 2600 सिगरेट जापान में, 1760 सिगरेट रूस में तथा 1000 सिगरेट इण्डोनेशिया में प्रतिव्यक्ति द्वारा एक साल में पी जाती हैं! सिगरेट की ही तरह गुटखा खैनी का व्यापार 5000 करोड़ रुपये का है। भारत में 32000 शराब की दुकानें हैं जिनसे 20000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बिकती है। यह केवल सरकारी आँकड़ा है, अभी इसमें वो दुकानें और आमदनी नहीं जोड़ी गई है जो अवैध शराब के जरिए होती है। वह आंकड़ा हमेशा अनिश्चित ही रहता है।

मौत का व्यापार करने में सबसे अधिक मुनाफा अगर किसी क्षेत्र में है तो वो है दवाएं। 1970 के दशक में डॉक्टर हाथी नाम के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया जिसका काम यह पता लगाना था कि भारत के लोगों को मूल रूप से कितनी तरह की दवाइयों की नितांत आवश्यकता है। इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि भारतीयों को 117 दवाओं से अधिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक कानून बनाया गया श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार में जिसमें इन मौलिक दवाइयों को स्वदेशी कंपनियाँ बनाने लगीं। इस कानून के फलस्वरूप दवाइयाँ सस्ती हो गईं और गरीबों की पहुँच में हो गईं। इसके बाद WHO की तरफ से कुछ विशेषग्य भारत में आए और उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि पिछले कुछ समय से दुनिया में नयी बीमारियाँ आ गई हैं जिसके लिए हाथी कमीशन की रिपोर्ट में संशोधन करने पड़ेंगे। WHO के डॉक्टरों ने एक नयी सूची जारी की और उसमें भारतीयों के लिए नितांत आवश्यक दवाएं डालीं। उनकी सूची में 450 दवाइयाँ रखी गईं। ये सूचियाँ इसीलिए जारी की गईं ताकि सरकार को यह पता रहे कि भारत में कितने पैमाने पर दवाओं का निर्माण होना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीयों को 450 से अधिक दवाओं की आवश्यकता नहीं है जिसमें सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाई शामिल है।

पिछले 13 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार में हज़ारों विदेशी कंपनियाँ इस क्षेत्र में कूद पड़ी हैं और सरकार ने इन मूलभूत दवाइयों का ठेका भी इन्हीं विदेशी कंपनियों को दे दिया है। दवाइयों का क्षेत्र इतना संवेदनशील होता है कि उसका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में देने का मतलब अपने गले में फंदा लगाने जैसा है! उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में कहीं महामारी फैल जाती है और उस महामारी की दवाई का अधिकार केवल एक विदेशी कंपनी के पास है। ऐसी स्थिति में वो कंपनी 25 पैसे की दवाई 2500 रूपए में दे सकती है! इस स्थिति में सरकार के पास दो ही विकल्प रह जाएँगे, या तो मुंहमांगे दाम को चुकाने के लिए विदेशी कर्ज़ ले अपमानजनक शर्तों पर या फिर अपने लोगों को तड़प तड़प कर मरने दे! मजे की बात तो यह है कि दवाओं के मूल्य को

नियंत्रित रखने के लिए भारत में एक विभाग हुआ करता था जिसे DPCO (Drug Price Control Order) कहते थे जिसे खुद मनमोहन सिंह ने ही बंद करवाया था ताकि बेरोकटोक विदेशी कंपनियाँ भारत को लूट सकें! दवाओं में 20000% तक का मुनाफा होता है। सरकार खुद कहती है कि भारत में केवल 35% लोग ही चिकित्सा व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं, बाकी सब ओझा और झाड़ू फूँक वालों के पास जाते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था ही ऐसी है कि ये 65% लोग अपने पैसे एक वक्त की रोटी खाने के लिए बचा पाते हैं और बीमारियों के लिए भगवान भरोसे रहते हैं!

भारत में पेटेंट कानून को संशोधित कर उसे इस तरह से ढाला गया था जिससे स्वदेशी कंपनियाँ बहुत सस्ते दाम पर बहुत अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ बनाने लगी थीं। मनमोहन सरकार ने विदेशी दबाव में आकर GATE समझौते पर हस्ताक्षर करके सन 2005 में पेटेंट कानून को फिर से संशोधित किया है। इस बार जो संशोधन हुए हैं उसने भारत के दवा उद्योग को पूरी तरह से चौपट कर देने का बीड़ा उठाया है! इसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं:

1. पेटेंट की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।
2. विदेश में दवाई बनाकर भारत में बेचने पर भी पेटेंट मिल सकता है।
3. पेटेंट अब उत्पाद पर भी दिया जाने लगा है और प्रक्रिया पर भी।
4. कोई भी कंपनी एक ही दवाई को कई नाम से बनाकर बेच सकती है।
5. अब खोज पर भी पेटेंट मिल सकता है जो पहले केवल आविष्कार पर ही मिलता था।
6. कोई भी विदेशी कंपनी जरूरी और गैर जरूरी दवा पर पेटेंट ले सकती है और उसे किसी भी स्वदेशी कंपनी को निगल लेने का अधिकार प्राप्त है।

भारत की एक बहुत मशहूर दवा बनाने वाली एक कंपनी थी Ranbaxy, जिसने भारत के निर्यात को कई गुणा बढ़ाया था और भारत का नाम विश्वपटल पर स्थापित किया था। अमरीका की एक कंपनी Eli Lilly ने वर्तमान पेटेंट कानून

की बदौलत Ranbaxy को रातों रात खरीद लिया! इससे हुआ यह कि अब यह कंपनी धड़ल्ले से कितने भी profit margin पर दवा बना सकती है और थोड़ा सा फेरबदल कर दोबारा उसी दवाई पर पेटेंट ले सकती है! इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक भी मंत्री ऐसा नहीं जो इसके खिलाफ आवाज उठा सके! आपको अपनी आन, बान और शान की सौगंध है कि इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को संसद से उखाड़कर बाहर फेंकें वरना वो दिन दूर नहीं जब यह देश फिर से गुलाम हो जाएगा!

“बहिष्कार वो dynamite है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ तो उड़ा सकता है!”

- महात्मा गाँधी

इन्कलाब जिंदाबाद!

वंदे मातरम...